



Most Trusted Learning Platform

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),

CURRENT AFFAIRS

DISCUSSION

Questions for Practice

Consider the following statements regarding Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure

1. It aims to provide better ways of measuring planet-warming pollution and help inform policy choices.
2. It will integrate space-based and surface-based observing systems
3. It has been launched by the United Nation Environment Program.

How many statements given above is/are correct?

- a. Only one
- b. Only two
- c. All three
- d. None

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- ✓ 1. इसका उद्देश्य ग्रह-वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीति विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है।
- ✓ 2. यह अंतरिक्ष-आधारित और सतह-आधारित अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करेगा
- ✗ 3. इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया है।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं/हैं?

एक। केवल एक

✓ बी। सिर्फ दो

सी। सभी तीन

डी। कोई नहीं

Questions for Practice

The NAMASTE scheme is a joint Scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment along with

- a. Ministry of Health and Family Welfare**
- b. Ministry of Panchayati Raj**
- c. Ministry of Rural Development**
- d. Ministry of Housing and Urban Affairs**

नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त योजना है

- a. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ**
- b. पंचायती राज मंत्रालय के साथ**
- c. ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ**
- d. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के साथ**

Questions for Practice

Sickle cell Anemia is

- a. Deficiency Disease**
- b. Genetic Disease**
- c. Communicable Disease**
- d. None**

सिकल सेल एनीमिया है

- a. पोषक तत्वों की कमी से बीमारी**
- b. आनुवंशिक रोग**
- c. संक्रामक रोग**
- d. कोई नहीं**

Questions for Practice

Which of the following is not considered as part of Lithium Triangle?

- A. Argentina
- B. Bolivia
- C. Chile
- D. Venezuela

निम्नलिखित में से किसे लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं माना जाता है? लिथियम त्रिभुज का भाग

- a. अर्जेंटीना
- b. बोलीविया
- c. चिली
- ✓ d. वेनेजुएला

Questions for Practice

Consider the following statements with respect to Vayulink System

1. It uses NAVIC to send radio communication to the base station when the signals are low.
2. It prevents aircraft collision and provides better combat teaming
3. India has acquired the vayulink system from Israel

How many statements given above is/are correct?

- a. Only one
- b. Only two
- c. All three
- d. None

Consider the following statements with respect to Vayulink System

- ☒ 1. It uses NAVIC to send radio communication to the base station when the signals are low.
- ☒ 2. It prevents aircraft collision and provides better combat teaming
- ☒ 3. India has acquired the vayulink system from Israel

How many statements given above is/are correct?

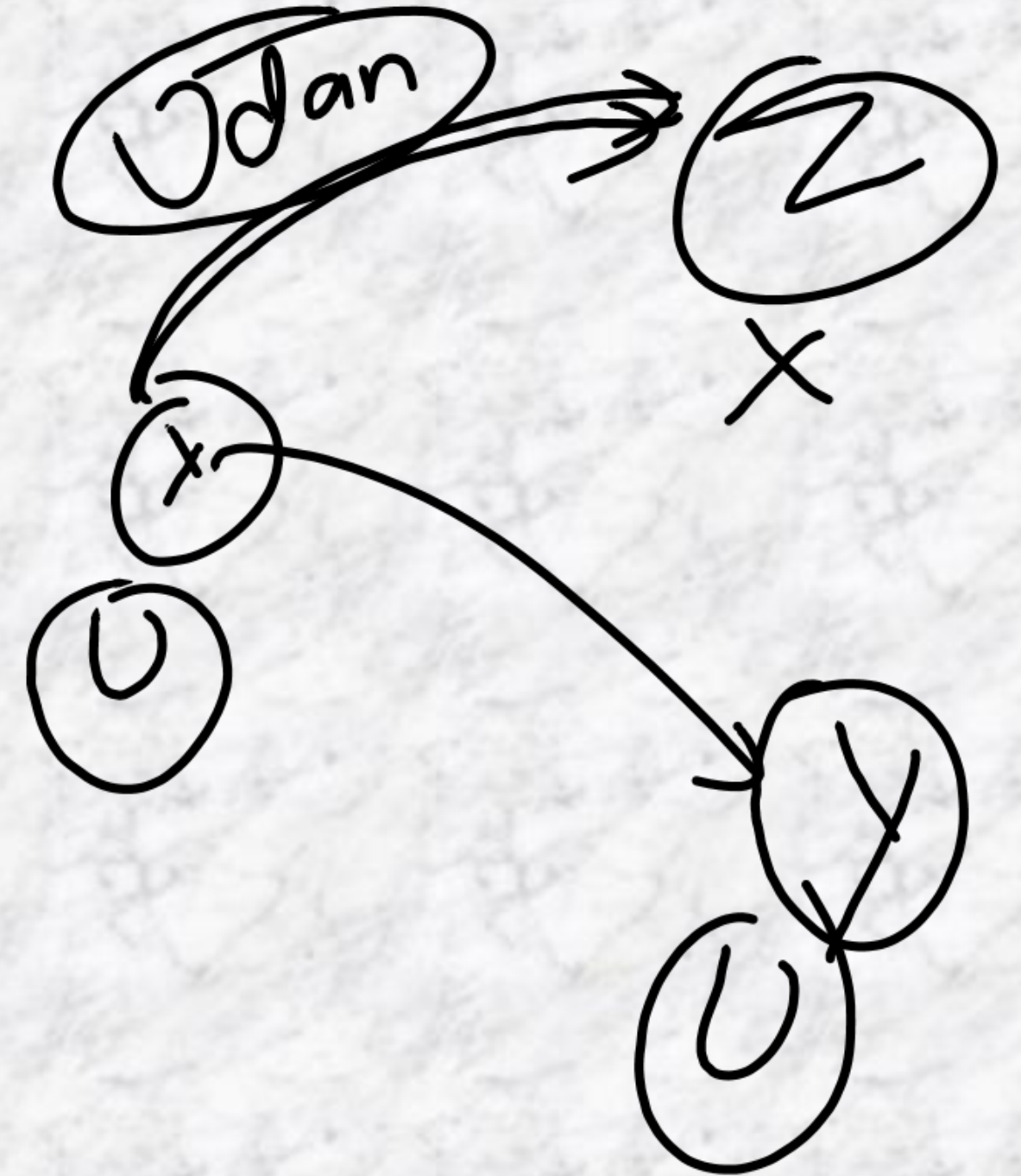
- a. Only one
- ☒ b. Only two
- c. All three
- d. None

❖ उड़ान 5.0

UDAN → Uda
 desh
 Ke
 Aam
 Nagrik

- UDAN 1.0: 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों (36 नव निर्मित परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिए 128 उड़ान मार्ग प्रदान किये गए
- UDAN 2.0: 73 अंडरसर्व्स और अनसर्व्स हवाई अड्डों की घोषणा की गई और पहली बार हेलीपैड भी जोड़े गए।
- UDAN 3.0: पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। वॉटर एयरोड्रोम को जोड़ने के लिए सीप्लेन के अलावा, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के कई मार्ग इस योजना के दायरे में आए।
- उड़ान 4.0: उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्रोत्साहन दिया गया। हेलीकाप्टरों और समुद्री विमानों का संचालन शामिल किया गया।
- UDAN 5.0 जहां श्रेणी-2 (20-80 सीटें) और श्रेणी-3 (>80 सीटें) विमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- इसी तरह, 600 किमी की सीमा हटा दी गई है और उड़ान के आरंभ और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है
- एक प्रमुख अद्यतन ऑपरेटरों के लिए विस्तारित परिचालन दायरा है, जो उन मार्गों को अनुमति देता है जहां मूल या गंतव्य स्थान प्राथमिकता क्षेत्र में आता है। पहले, अर्हता प्राप्त करने के लिए दोनों बिंदुओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होना पड़ता था।
- इसके अतिरिक्त, इस योजना ने यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा को और अधिक किफायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा को 25 प्रतिशत तक कम कर दिया है।



❖ UDAN 5.1

- **UDAN 1.0:** 5 airlines companies were awarded 128 flight routes to 70 airports (including 36 newly made operational airports)
- **UDAN 2.0:** 73 underserved and unserved airports were announced and for the first time, helipads were also connected.
- **UDAN 3.0:** In coordination with the Ministry of Tourism, Tourism Routes were included. In addition to Seaplanes for connecting Water Aerodromes, several routes in the North-East Region came under the ambit of the scheme.
- **UDAN 4.0:** Gave impetus to North-Eastern Regions, Hilly States, and Islands. The operation of helicopters and seaplanes incorporated.
- **UDAN 5.0** where the focus is on Category-2 (20-80 seats) and Category-3 (>80 seats) aircraft.

- **Similarly, the cap of 600 km has been removed and there is no restriction on the distance between the origin and destination of the flight**
- **One key update is the expanded operational scope for operators, allowing routes where either the origin or destination location falls within a priority area. Previously, both points had to be in priority areas to qualify.**
- **Additionally, the scheme has reduced airfare caps by up to 25 percent to make helicopter travel more affordable for passengers.**

➤ लॉन्ड्रोमैट देश ✓

- "लॉन्ड्रोमैट" देश वे देश हैं जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदते हैं, इसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, और फिर यूरोप और अन्य जी7 देशों में इन्हें "लॉन्डर" करते हैं।
- सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के अनुसार, पांच "लॉन्ड्रोमैट" देश हैं: भारत, चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर।
- ये देश रूस के 70% कच्चे तेल निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं।
- "लॉन्ड्रोमैट" देशों ने खुले तौर पर उन प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया है जो पश्चिम द्वारा रूस पर लगाए गए थे।
- नतीजतन, ये देश रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं।
- प्राइस कैप गठबंधन देशों में 3.7 मिलियन टन रिफाइंड तेल उत्पादों के अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरा। यह 2021 से 0.3 मिलियन टन की वृद्धि है।
- प्राइस कैप गठबंधन (पीसीसी), ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू, जापान, यूके और यूएस से बना है।
- उन्होंने तीन अलग-अलग मूल्य सीमाएं पेश की हैं, जो वर्तमान में लागू हैं और समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

Price
Cap
Coalition

Laundromat Countries

"Laundromat" countries are nations that purchase cheap crude oil from Russia, convert it into refined petroleum products, and then "launder" these in Europe and other G7 countries.

According to the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), the five "laundromat" countries are: India, China, Turkey, UAE, Singapore.

These countries are responsible for 70% of Russia's crude oil exports.

The "laundromat" countries have openly bypassed the sanctions that were imposed by the West on Russia.

As a result, these countries have been purchasing crude oil from Russia at a cheaper price.

In 2022, India emerged as the leading exporter of refined oil products at 3.7 million tonnes to Price Cap Coalition countries. This is an increase of 0.3 million tonnes from 2021.

The Price Cap Coalition (PCC), composed of Australia, Canada, the EU, Japan, the UK, and the US,

- They have introduced three different price caps, which are currently in force and subject to periodic revision.
- The mechanism agreed by PCC set one price cap for Russian oil (3 December 2022) and two caps for petroleum products shipped to third countries (4 February 2023).
- This mechanism helps addressing inflation and keeping energy costs stable.
- The price caps prohibit operators from members of the PCC to trade, broker or transport petroleum products that originate in or that have been exported from Russia to third countries, unless they are sold at or below the price caps.
- They also prohibit the provision of services (e.g. insurance) or financial assistance related to this trading, brokering or transporting, unless the petroleum products are sold at or below the price caps.

- पीसीसी द्वारा सहमत तंत्र ने रूसी तेल के लिए एक मूल्य सीमा (3 दिसंबर 2022) और तीसरे देशों को भेजे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के लिए दो सीमाएँ (4 फरवरी 2023) निर्धारित कीं।
- यह तंत्र मुद्रास्फीति को संबोधित करने और ऊर्जा लागत को स्थिर रखने में मदद करता है।
- मूल्य सीमाएं पीसीसी के सदस्यों के ऑपरेटरों को उन पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करने, दलाली करने या परिवहन करने से रोकती हैं जो रूस में उत्पन्न होते हैं या जिन्हें रूस से तीसरे देशों में निर्यात किया गया है, जब तक कि उन्हें मूल्य सीमा पर या उससे नीचे नहीं बेचा जाता है।
- वे इस व्यापार, दलाली या परिवहन से संबंधित सेवाओं (जैसे बीमा) या वित्तीय सहायता के प्रावधान पर भी रोक लगाते हैं, जब तक कि पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य सीमा पर या उससे नीचे नहीं बेचे जाते।

- ❖ **Great pacific garbage patches**

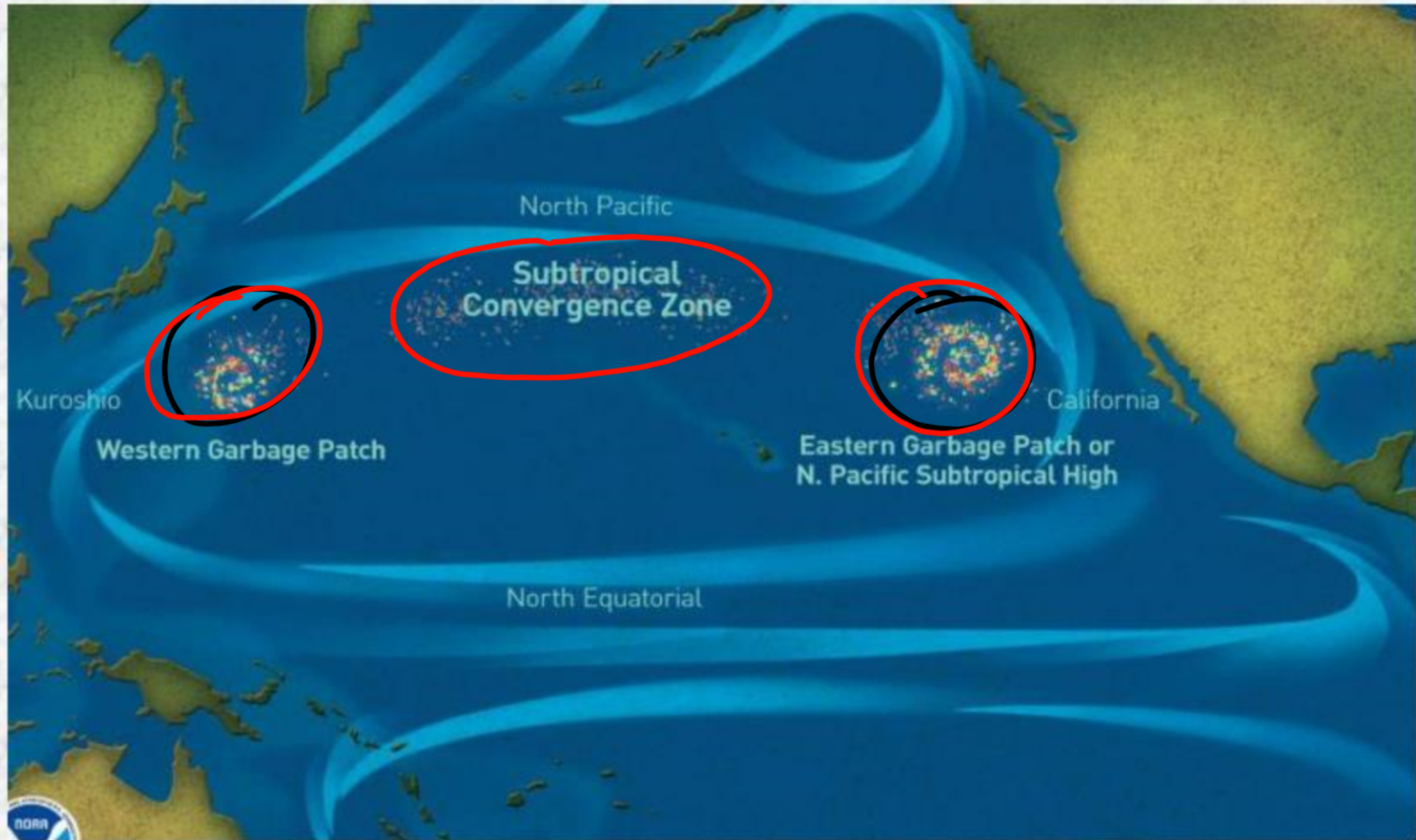
- ❖ **The Great Pacific Garbage Patch is a collection of marine debris in the North Pacific Ocean.**

- **Also known as the Pacific trash vortex, the garbage patch is actually two distinct collections of debris bounded by the massive North Pacific Subtropical Gyre.**
- **The Great Pacific Garbage Patch, also known as the Pacific trash vortex, spans waters from the West Coast of North America to Japan.**
- **The patch is actually comprised of the Western Garbage Patch, located near Japan, and the Eastern Garbage Patch, located between the U.S. states of Hawai'i and California**
- **The circular motion of the gyre draws debris into this stable center, where it becomes trapped.**

❖ महान प्रशांत कचरा पैच

❖ ग्रेट प्रशांत कचरा पैच उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संग्रह है।

- प्रशांत कचरा भंवर के रूप में भी जाना जाता है, कचरा पैच वास्तव में विशाल उत्तरी प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय गियर द्वारा घिरे मलबे के दो अलग-अलग संग्रह हैं।
- ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच, जिसे प्रशांत कचरा भंवर के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से जापान तक पानी तक फैला हुआ है।
- पैच वास्तव में जापान के पास स्थित पश्चिमी कचरा पैच और अमेरिकी राज्यों हवाई और कैलिफ़ोर्निया के बीच स्थित पूर्वी कचरा पैच से बना है।
- गाइर की गोलाकार गति मलबे को इस स्थिर केंद्र में खींचती है, जहां वह फंस जाता है।



❖ Meri LiFE App

- MeriLiFE empowers individuals to lead a sustainable lifestyle by making pro-planet choices in their daily lives.
- The app is inspired by the concept of LiFE, introduced by the Honourable Prime Minister at COP 26,
- The concept of LiFE emphasizes mindful and deliberate utilization instead of mindless and wasteful consumption.
- The Meri LiFE mobile application aims to enable a greater community of young people to emerge as Pro-Planet-Persons, changemakers and solution providers towards some of the greatest environmental problems we are confronted with today, through phygital mediums.

- **Meri LiFE is a marketplace where young people can explore their interests, find Climate Change and Environmental Sustainability focused opportunities that match their interests, and sign up to act on issues that matter the most to them**

❖ मेरी लाइफ ऐप

- मेरिलाइफ व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में ग्रह-अनुकूल विकल्प चुनकर एक स्थायी जीवन शैली जीने का अधिकार देता है।
- LiFE की अवधारणा से प्रेरित है , जिसे COP 26 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया था।
- LiFE की अवधारणा बिना सोचे-समझे और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर जोर देती है।
- मेरी लाइफ मोबाइल एप्लिकेशन का उद्देश्य युवा लोगों के एक बड़े समुदाय को भौतिक माध्यमों के माध्यम से उन कुछ सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रो-प्लैनेट-पर्सन, चेंजमेकर्स और समाधान प्रदाताओं के रूप में उभरने में सक्षम बनाना है, जिनका हम आज सामना कर रहे हैं।

UNFCCC

- मेरी लाइफ़ एक बाज़ार है जहां युवा अपनी रुचियों का पता लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित अवसर ढूंढ सकते हैं जो उनकी रुचियों से मेल खाते हैं, और उन मुद्दों पर कार्य करने के लिए साइन अप कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।

❖ Bluebugging

- **Bluebugging is a hacking technique that allows attackers to access a device with a Bluetooth connection.**
- **Once the device accesses a compromised link, the attacker can take full control of it**
- **Bluebugging can target devices such as phones, tablets, laptops, and even earphones, speakers, and smartwatches.**
- **It's conducted by exploiting a security flaw in the Bluetooth protocol.**
- **Once a device is blue-bugged, the entire control of the phone is accessible to the hacker.**
- **The hackers can retrieve all the data including messages, calls, and sensitive information from the device.**

❖ ब्लूबगिंग

- ब्लूबगिंग एक हैकिंग तकनीक है जो हमलावरों को ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ डिवाइस तक पहुंचने की अनुमति देती है।
- एक बार जब डिवाइस किसी हैक किए गए लिंक तक पहुंच जाता है, तो हमलावर उस पर पूरा नियंत्रण ले सकता है
- ब्लूबगिंग फोन, टैबलेट, लैपटॉप और यहां तक कि इयरफ़ोन, स्पीकर और स्मार्टवॉच जैसे उपकरणों को लक्षित कर सकती है।
- यह ब्लूटूथ प्रोटोकॉल में एक सुरक्षा दोष का फायदा उठाकर संचालित किया जाता है।
- एक बार जब कोई डिवाइस ब्लू-बग हो जाता है, तो फोन का पूरा नियंत्रण हैकर के पास पहुंच जाता है।
- हैकर्स डिवाइस से संदेश, कॉल और संवेदनशील जानकारी सहित सभी डेटा पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।

❖ **Space science and Technology AwaReness Training (START)**

- **ISRO has launched a new introductory-level online training programme called 'Space Science and Technology Awareness Training (START)'**
- **It is aimed at post-graduate and final-year undergraduate students of physical sciences and technology.**
- **The programme will cover various domains of space science, including Astronomy & Astrophysics, Heliophysics & Sun-Earth interaction, Instrumentation, and Aeronomy.**
- **It will be delivered by the scientists from Indian academia and ISRO centres.**

❖ Eligibility of Candidates

- **Category-1:** Post-graduate students and final year under graduate students of physical sciences (Physics and Chemistry) and technology (e.g. Electronics, Computer Science, Mechanical, Applied Physics, Radiophysics, Optics & Opto-electronics, Instrumentation and other associated subjects) studying in Indian educational institutes/Universities/Colleges are eligible to be considered for the training.
- **Category-2:** Interested individual participants (including students who are not eligible / could not join through the category-1) of any background can directly register and attend the live sessions through Youtube Channel of IIRS

❖ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)

- इसरो ने 'अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)' नामक एक नया परिचयात्मक-स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।
- इसका ध्यान भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों पर केंद्रित हैं।
- कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन को कवर करेगा, जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य-पृथ्वी इंटरैक्शन, इंस्ट्रुमेंटेशन और एरोनॉमी शामिल हैं।
- इसे भारतीय शिक्षा जगत और इसरो केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा वितरित किया जाएगा।

❖ अभ्यर्थियों की पात्रता

- श्रेणी-1: रेडियोफिजिक्स , ऑप्टिक्स और ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन और अन्य संबंधित विषय) के स्नातकोत्तर छात्र और स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र प्रशिक्षण के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।
- श्रेणी-2: किसी भी पृष्ठभूमि के इच्छुक व्यक्तिगत प्रतिभागी (उन छात्रों सहित जो पात्र नहीं हैं/श्रेणी-1 में शामिल नहीं हो सकते हैं) सीधे पंजीकरण कर सकते हैं और आईआईआरएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव सत्र में भाग ले सकते हैं।

❖ India and Asian Development Bank: Country partnership strategy (CPS)

- **The Asian Development Bank (ADB) has launched a new country partnership strategy (CPS) for India.**
- **The partnership will focus on deepening its engagement with the nation, while simultaneously supporting India's drive for robust, climate-resilient, and inclusive growth.**
- **It will also focus on accelerating structural transformation and job creation, promoting climate-resilient growth, and deepening social and economic inclusiveness, during its partnership period 2023-2027.**

- **ADB has announced to contribute to the nation's national flagship programmes on developing industrial corridors, multimodal logistics systems, urban infrastructure, skill ecosystem, and small businesses.**

❖ Asian Development Bank

- **The Asian Development Bank (ADB) is a multilateral development bank that aims to reduce poverty in Asia and the Pacific.**
- **It was established in 1966 and is headquartered in the Philippines.**
- **It has 68 members, 49 from Asia and the Pacific and 19 from outside**
- **India is among the founding members of this Bank**
- **US and Japan (15.6% each) are the largest shareholders of ADB in non-borrowing category**
- **China (6.4%) and India (6.3%) are the largest shareholders of ADB in borrowing category**

❖ भारत और एशियाई विकास बैंक: देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस)

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत के लिए एक नई देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) शुरू की है।
- साझेदारी राष्ट्र के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही मजबूत, जलवायु-लचीला और समावेशी विकास के लिए भारत के अभियान का समर्थन करेगी।
- यह अपनी साझेदारी अवधि 2023-2027 के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाने, जलवायु-लचीला विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक समावेशन को गहरा करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- एडीबी ने औद्योगिक गलियारों, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, शहरी बुनियादी ढांचे, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र और छोटे व्यवसायों के विकास पर देश के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों में योगदान देने की घोषणा की है।

❖ एशियाई विकास बैंक

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका लक्ष्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करना है।
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है।
- इसके 68 सदस्य हैं, 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से और 19 बाहर से
- भारत इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है
- अमेरिका और जापान (प्रत्येक 15.6%) गैर-उधार श्रेणी में एडीबी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं
- चीन (6.4%) और भारत (6.3%) उधार श्रेणी में एडीबी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं

❖ NATO Plus

- **The North Atlantic Treaty Organization is a military alliance of 31 nations, mainly the US and some European countries.**
- **NATO Plus includes five more member nations considered allies of the US – namely: Australia, Japan, South Korea, New Zealand and Israel**
- **The platform was formalized in 2019 and its primary goal is to enhance defence cooperation among NATO's global partners.**

❖ What is NATO?

- It is an intergovernmental military alliance, established by the North Atlantic Treaty (Washington Treaty) of 1949, to provide collective security against the Soviet Union.
- There are currently 31 member states. Its original members were Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom, and the United States. Finland is the newest member.
- NATO membership is open to “any other European state in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area.”
- NATO is committed to the principle that an attack against one or several of its members is considered as an attack against all. This is the principle of collective defence, which is enshrined in Article 5 of the Washington Treaty. So far, Article 5 has been invoked once - in response to the 9/11 terrorist attacks in the United States in 2001.

❖ नाटो प्लस

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 31 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं।
- नाटो प्लस में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले पांच और सदस्य देश शामिल हैं - अर्थात्: ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इज़राइल
- मंच को 2019 में औपचारिक रूप दिया गया था और इसका प्राथमिक लक्ष्य नाटो के वैश्विक भागीदारों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है।

❖ नाटो क्या है?

- यह एक अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन है, जो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (वाशिंगटन संधि) द्वारा स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। फिनलैंड सबसे नया सदस्य है।
- नाटो की सदस्यता "किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है।"
- नाटो इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है कि उसके एक या कई सदस्यों के खिलाफ हमले को सभी के खिलाफ हमला माना जाता है। यह सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है, जो वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है। अब तक, अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया है - 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के जवाब में।

❖ BUSINESS READY (B-READY) PROJECT

- **The World Bank Group is implementing a new corporate flagship, B-READY**
- **It aims to measure the business and investment climates in 180 economies worldwide annually**
- **The report aims to help countries attract investment and increase employment and productivity to accelerate development**
- **It replaces the World Bank Group's earlier Doing Business project,**
- **It focuses on ten topics that follow the life cycle of a firm, covering areas like including Business Entry, Business Location, Utility Services, Labor, Financial Services, International Trade, Taxation, Dispute Resolution, Market Competition, and Business Insolvency.**
- **The Business Ready project has been developed by a team of professionals both from inside and outside the World Bank Group, comprising members from governments, private entities, and civil society organizations.**

❖ बिजनेस रेडी (बी-रेडी) प्रोजेक्ट

- विश्व बैंक समूह एक नया कॉर्पोरेट फ्लैगशिप, बी-रेडी लागू कर रहा है
- इसका लक्ष्य सालाना दुनिया भर की 180 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल को मापना है
- रिपोर्ट का उद्देश्य देशों को विकास में तेजी लाने के लिए निवेश आकर्षित करने और रोजगार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना है
- यह विश्व बैंक समूह की पूर्व डूइंग बिजनेस परियोजना का स्थान लेता है।
- यह दस विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक फर्म के जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, जिसमें बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और बिजनेस दिवालियापन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को विश्व बैंक समूह के अंदर और बाहर के पेशेवरों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें सरकारों, निजी संस्थाओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्य शामिल हैं।

❖ **CITIIS 2.0**

- **City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (CITIIS 2.0) is a four-year program that runs from 2023 to 2027.**
- **It is part of the Government of India's Smart Cities Mission and aims to promote integrated waste management and climate-oriented reform.**
- **The CITIIS 2.0 will be implemented in 18 cities which would be selected based on a competition.**
- **It would span over a period of four years from 2023-2027 and has been conceived and would be implemented in partnership with the French Development Agency (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), the European Union (EU), and National Institute of Urban Affairs (NIUA)**
- **The funding for CITIIS 2.0 would include a loan of Rs 1760 crore from AFD and KfW, split equally, and a technical assistance grant of Rs 106 crore from the European Union**

❖ (CITIIS 2.0)

- ❖ सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0) एक चार साल का कार्यक्रम है जो 2023 से 2027 तक चलता है।
 - यह भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज़ मिशन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु-उन्मुख सुधार को बढ़ावा देना है।
 - CITIIS 2.0 को 18 शहरों में लागू किया जाएगा जिनका चयन एक प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा।
 - इसकी अवधि 2023-2027 तक चार वर्षों की होगी और इसकी कल्पना की गई है और इसे फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),) (केएफडब्ल्यू), यूरोपीय संघ (ईयू) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा।

- KfW से समान रूप से विभाजित 1760 करोड़ रुपये का ऋण और यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपये का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा।



❖ **Logistics Performance Index (LPI) Report, 2023,- JNP port**

- **Context:** Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), India's leading container port, has achieved a global milestone in container cargo handling with a remarkable turnaround time (TAT) of only 22 hours, the World Bank's 2023 Logistics Performance Index (LPI)
- **Released by :** World Bank
- **India's rank – 38/139**
- **India was ranked 44th on the index in 2018 and has now climbed to 38th in the 2023 listing. India's performance has drastically improved from 2014, when it was ranked 54th on the LPI.**
- **Till 2018, it was a biennial report.**

➤ **The LPI report evaluates countries' trade logistics performance across six dimensions:**

- **clearance process efficiency,**
- **quality of trade and transport-related infrastructure,**
- **ease of arranging competitively priced shipments,**
- **competence and quality of logistics services,**
- **ability to track and trace consignments, and**
- **frequency of on-time consignee deliveries.**

❖ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रिपोर्ट, 2023,- जेएनपी पोर्ट

- संदर्भ: भारत के अग्रणी कंटेनर बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) ने विश्व बैंक के 2023 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) के अनुसार, केवल 22 घंटे के उल्लेखनीय टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के साथ कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में एक वैश्विक मील का पत्थर हासिल किया है।
- द्वारा जारी: विश्व बैंक
- भारत की रैंक- 38/139
- भारत 2018 में सूचकांक में 44वें स्थान पर था और अब 2023 की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के प्रदर्शन में 2014 से काफी सुधार हुआ है, जब यह एलपीआई पर 54वें स्थान पर था।
- 2018 तक यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट थी।

➤ एलपीआई रिपोर्ट छह आयामों में देशों के व्यापार लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है:

- निकासी प्रक्रिया दक्षता,
- व्यापार और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता,
- प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले शिपमेंट की व्यवस्था करने में आसानी,
- रसद सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता,
- खेपों को ट्रैक करने और उनका पता लगाने की क्षमता, और
- समय पर कंसाइनी डिलीवरी की आवृत्ति।



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

